



Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

## INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

E-mail : [hr@innovativetechin.com](mailto:hr@innovativetechin.com) • Website : [www.innovativetechin.com](http://www.innovativetechin.com) • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges & \*Pay Money after the visa

### IELTS • STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA

U.K SINGAPORE EUROPE

## हरियाणा पुलिस ने 3 आईईडीज़ व पिस्तौल समेत 4 व्यक्ति किए गिरफ्तार

## कोविड खत्म होने के बाद लागू होगा सीएए : अमित शाह

डीजीपी वीके भावरा ने कहा- पंजाब पुलिस की टीमों पहले ही फाजिल्का से मुलजिम्ओं का कर रही थी पीछा

• जालंधर ब्रीज, चंडीगढ़

एक संगठित और पूर्ण तालमेल भरपूर कार्यवाही के अंतर्गत, पंजाब पुलिस ने गुरुवार को दोषियों का 300 किलोमीटर से अधिक दूर तक पीछा करके और चार शककी व्यक्तियों की गिरफ्तारी से एक संभावित आतंकवादी हमले को टालने में बड़ी सफलता हासिल की है। इन व्यक्तियों के पास से 3 आईईडीज़ जो एक मेटलिक केस (2.5 किलो प्रत्येक) में पैक किये गए थे, 1 पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किया गया है। दोषियों की पहचान गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह और परमिन्दर सिंह तीनों निवासी गाँव विजोके, जीरा, फिरोज़पुर और लुधियाना के गाँव भट्टियाँ के भूपिन्दर सिंह के तौर पर हुई है। हरियाणा पुलिस ने उक्त व्यक्तियों को पंजाब पुलिस की सूचना पर कर्नाल से गिरफ्तार किया गया है।



व्यक्तियों के होने संबंधी जानकारी मिली थी, जिन पर पुलिस को शक है कि वह विस्फोटक सामग्री और हथियार लेजा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उक्त जानकारी के बाद, कमांडेंट पीएपी हरकमलप्रीत सिंह खख और एस.एच.ओ. एस.एस.ओ.सी. फाजिल्का सतिन्दरदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व वाली पुलिस टीमों से तरफ केंद्रीय एजेंसी की टीमों के साथ मिल कर इन शकियों को काबू करने के लिए बुधवार और गुरुवार को बीच का रात को छापेमारी की गई। इन टीमों ने सांझे तौर पर फिरोज़पुर, फाजिल्का, फरीदकोट और एस्पएएस नगर जिलों में शककी टिकानों की पहचान की थी।

हरियाणा पुलिस के साथ संपर्क बनाया जिसके अंतर्गत कर्नाल में वाहन को रोक कर मुलजिम्ओं को आईईडी समेत गिरफ्तार किया गया।" प्राथमिक पूछताछ के दौरान मुलजिम्ओं ने कबूला कि वह पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा के लिए काम करते थे। ज़िक्रयोग्य है कि रिन्दा जो कि पंजाब, चण्डीगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा में सक्रिय एक मशहूर गैंगस्टर है और पंजाब पुलिस को कत्ल, कंट्रेक्ट कोलिंग, डकैती, फिरौती और सनेचिंग जैसे कई घृणित अपराधों में वांछित है। बताने योग्य है कि कर्नाल के मधुवन पुलिस थाने में दर्ज की गई एफ.आई.आर. के मुताबिक एस.एस.ओ.सी. फाजिल्का के एस.एच.ओ. सतीन्द्र सिंह बराड़ ने हरियाणा पुलिस को सूचना दी थी कि एक सफ़ेद रंग की इनोवा कार शककी रूप में विस्फोटक लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रही है। जिसके उपरांत पुलिस की टीमों को वाया टोल प्लाज़ा और नाका लगाने के लिए भेजा गया और वाहनों की चैकिंग के दौरान मुलजिम्ओं को गोला-बारूद समेत गिरफ्तार कर लिया गया।

कोलकाता. बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून को लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कहा, "गृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अफवाह फैला रही है कि सीएए लागू नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना



के बाद हम सीएए लागू करेंगे।" अमित शाह ने कहा कि सीएए हकीकत था, सीएए हकीकत है और सीएए हकीकत रहेगा। कुछ भी नहीं बदला है। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक था जिसने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था।

केंद्रीय मंत्री ने बंगाल में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि दीदी ने बीरभूम में नौ लोगों को जिंदा जला दिया। शाह ने कहा, "ममता दीदी, आपको बंगाल के लोगों ने तीन बार चुना है और हमने सोचा था कि आप खुद को सुधारेंगे लेकिन आपने नहीं किया। मैं वादा करता हूँ कि जब तक आप 'कट मनी' और हिंसा नहीं रोकेंगे, भाजपा इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। शाह ने कहा कि चुनाव के बाद की हिंसा के बाद, मानवाधिकार

आयोग ने कहा कि यहाँ कानून का शासन नहीं था, यहाँ केवल शासक का शासन था। 100 से अधिक हत्याएँ, 1,829 घायल और टीएमसी के लोग 161 मामलों में शामिल थे। शाह पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बंगाल के दौरे पर हैं। 6 मई को अमित शाह कूचबिहार के श्री बीधा कॉरिडोर पर बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर में गृह मंत्री कोलकाता पहुंचेंगे और पार्टी विधायकों और राज्य भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

## नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर

चंडीगढ़. पंजाब में होने वाले आगामी नगर निगमों के चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने कमर कस ली है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी जर्नेल सिंह ने पार्टी के राज्य महासचिव हरचंद सिंह बरसट और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर आगामी नगर निगम चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा की। आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में और भी बेहतर मौका है। आप पंजाब के प्रभारी जर्नेल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी निगम की सभी सीटों पर ईमानदार उम्मीदवार उतारेंगे। आम जन की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है और उनके स्थाई समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

## समूची भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से पूरा किया जाएगा : भगवंत मान

अगले बजट में कई और जन-समर्थक पहल करने का किया ऐलान

• जालंधर ब्रीज, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज 'आप' सरकार के 50 दिन पूरे होने पर बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम चलाने का ऐलान करते हुए योग्य उम्मीदवारों को उनकी शैक्षिक योग्यता के मुताबिक केवल मेरिट के आधार पर नौकरियाँ देने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूची भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से पूरी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में

कहा कि बड़े स्तर पर चल रही भर्ती मुहिम में सिफ़ारिश या रिश्तखोरी को कोई जगह नहीं मिलेगी। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 25 विभिन्न विभागों में 26,454 पदों के लिए भर्ती भ्रष्टाचार मुक्त और बिना किसी पक्षपात के की जाएगी। भगवंत मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही समाचार पत्रों में विस्तारपूर्वक विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें शैक्षिक योग्यता के अनुसार आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए खाली पड़े पदों की संख्या, भर्ती एजेंसियाँ (पी.पी.एस.सी./एस.एस.एस.बी./ तीसरा पक्ष/विभाग) और भर्ती के विवरण जानने के लिए

विभागीय वेबसाइटों के लिंक शामिल किए गए हैं। युवाओं के लिए रोजगार के बेशुमार अवसरों का वादा करते हुए भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में और नौकरियाँ भी लेकर आएगी, जिससे युवाओं को सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आजीविका कमाने के लिए सक्षम बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार द्वारा किए जाने वाले कई और जन-समर्थक पहलों का भी जिक्र किया, जिनका ऐलान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले वार्षिक आम बजट 2022-23 में किया जाएगा।

# प्रधानमंत्री आवास योजना : आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बावजूद नहीं सुधरे हालात

नगर निगम जालंधर में लोगों को किशतों के लिए करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना

• जालंधर ब्रीज, विशेष रिपोर्ट

केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्बन हाउसिंग के अंतर्गत की गयी थी जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना में सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की राशि केंद्र द्वारा राज्य सरकार के साथ मिल कर सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। इस राशि को देने के लिए अर्बन लोकल बॉडी में कार्य कर रही नगर निगम और अन्य सरकारी संस्था में लाभार्थी को अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है जिसके बाद उन्हें पहली किशत 50 हजार रुपए घर की नींव का स्तर पूरा होने पर, दूसरी किशत 50 हजार रुपए लिटल बीम तक कार्य पूरा होने पर, 20 हजार रुपए घर की छत डालने के बाद और आखिरी किशत 30 हजार रुपए घर पूरा होने के बाद दी जाती है। परन्तु नगर निगम जालंधर में लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली किशतों को लेने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।



बता दें कि इस योजना के लाभार्थियों द्वारा बताया गया है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपनी फाइल के बारे में जानने की जब भी कोशिश की तो उन्हें यह कह दिया जाता है कि आप की फाइल हमारे पास नहीं आई है, दोबारा अप्लाई करो। दूसरी ओर

एक लाभार्थी द्वारा कहा गया कि हमें पहली किशत आ गई है पर दूसरी किशत आने में कई महीने तक लगा दिए जाते हैं। क्योंकि किशत डालने से पहले नगर निगम के जूनियर इंजीनियर जिनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, द्वारा मौके पर दी गई फोटोग्राफ को चेक करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जिसके बाद उनके खाते में पैसे डाले जाते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए संबंधित अधिकारी कई महीने और कई बार तो साल तक लगा देते हैं। इस बारे में पड़ताल करने पर कई लाभार्थियों ने अपना नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि जब तक इससे संबंधित अधिकारी या कर्मचारी लाभार्थियों से मुंह मीठा करने के नाम पर रिश्त नहीं ले लेते तब तक उनकी फाइल ऊपर तक नहीं जाती और उनका काम अधर में लटका रहता है या अधिकारी कर्मचारी टाल-मटोल करते रहते हैं। जिक्रयोग्य है कि मजबूरी में कई लाभार्थियों ने अपने मकान तोड़ कर रहने के लिए किराये के घर लिए हुए हैं जिसका वे भारी भरकम किराया चुका रहे हैं। कइयों ने तो किशत न मिलने की वजह से प्राइवेट फाइनेंसर से भारी भरकम ब्याज पर पैसे लिए हुए हैं जिसका ब्याज देना ही उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। किशतें लेंट मिलने से उन्हें सामान भी महंगे भाव खरीदना पड़ता है।

गौरतलब है कि अडिस्टेंट प्रोजेक्ट अफसर निर्मलजीत कौर से पूछे जाने पर जवाब मिला कि पहले इलेक्शन के चलते फंड्स नहीं दिए गए और अब 2 करोड़ के करीब जो फंड्स आते हैं वह दो दिन में ही खत्म हो जाते हैं जिस पर उन्हें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चंडीगढ़ भेज कर ही आगे फंड्स मिलते हैं। इसका कागजी प्रोसेस 7 से 10 दिन का होता है। परन्तु चंडीगढ़ लोकल बॉडी में इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज बलदीप सिंह द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि फंड्स की कोई कमी नहीं है और उन्होंने फंड्स बढ़ाने के लिए निर्मलजीत कौर को डिमांड रेज की चिट्ठी भेजने को कहा है। अब आने वाले दिनों में देखा होगा कि गरीब लाभार्थी जो पिछले कई सालों में अपना मकान शुरू और पूरा करने के सपने देख रहे हैं उनके सपने कब सच होंगे और सरकार द्वारा इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देकर इस विभाग पर किसी सीनियर अधिकारी के निरक्षण के अंतर्गत लोगों को आ रही

मुश्किलों का हल कब तक करवाया जाएगा। इस सारे सिस्टम को ऑनलाइन कैसे किया जायेगा जिससे लाभार्थी ऑफिस में आकर अपनी फाइल पता कर सकें कि किसके पास पड़ो है और कब उनके खाते में सरकार द्वारा दी जा रही राशि मिल पायेगी। जिससे फील्ड में कार्य कर रहे अधिकारियों की ज़िम्मेवारी भी तय हो सके।



• जालंधर नगर निगम कार्यालय में अपनी फाइलों व रुकी हुई किशतों की जानकारी लेने के लिए एकत्रित हुए बुजुर्ग लाभार्थी।



## NEWS +

## सरकार पेश करेगी इंडियन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एमाजोन और वालमार्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर

ओएनडीसी के लॉन्च के साथ, सरकार का टारगेट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है।



भारत में अमेजन और वालमार्ट जैसी यूएस-आधारित ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए भारत सरकार डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नया ओएनडीसी प्लेटफॉर्म खरीदारों और सेलर को एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की सुविधा देगा। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को लॉन्च एमाजोन और वालमार्ट के कुछ फिलपकार्ट के डोमेस्टिक सेलर्स पर भारत के एंटीट्रस्ट बांडी छापे को देखते हुए आया है। कंपनी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। ओएनडीसी के लॉन्च के साथ, सरकार का टारगेट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है।

जानकारी के मुताबिक, ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म दिल्ली एनसीआर, बंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर सहित पांच शहरों में लॉन्च किया जाएगा। बाद में इसका विस्तार दूसरे शहरों में किया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मोदी सरकार और उसके प्रमुख समर्थकों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि अमेजन और फिलपकार्ट केवल कुछ बड़े सेलर को ही बनेफिट करते हैं। हालांकि, कंपनियों ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि वे भारत सरकार के निर्धारित कानूनों का पालन करें।

एमाजोन और फिलपकार्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर : हालांकि, एमाजोन और फिलपकार्ट ने अभी तक सरकार के ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की ओएनडीसी प्लान का टारगेट 30 मिलियन सेलर और 10 मिलियन मर्चेंट्स को ऑनलाइन जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार का टारगेट, अगस्त तक कम से कम 100 शहरों और कस्बों को कवर करने की योजना है। सरकार खरीदारों और सेलर्स के लिए लोकल भाषा में ऐप्स पर ध्यान केंद्रित करेगी।

## मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलने की स्वतंत्रता का स्थान बनाने के लिए खरीद रहे हैं

## ट्विटर खरीदने के लिए पैसा जुटा रहे एलन मस्क, टेस्ला के 44 लाख शेयर्स को लगभग चार अरब डॉलर में बेचा

टेस्ला के निवेशकों को यह आशंका है कि ट्विटर के कारण एलन मस्क का ध्यान टेस्ला से भटक जाएगा और इस इलेक्ट्रिक कार कंपनी के संचालन में उनकी दिलचस्पी कम हो जाएगी।

इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कंपनी के 44 लाख शेयर्स को 3199 बिलियन डॉलर (3,05,14,52,25,000 रुपये) में बेच दिया है। ब्लूमबर्ग ने फॉर्म 4 की फाइलिंग का हवाला देते हुए इसकी जानकारी दी है। इसने बताया, 'लगभग दो ट्रांजेक्शन की तारीखों पर होने वाले सभी 138 व्यक्तिगत लेनदेन को कवर करने के लिए फॉर्म 4 को पांच फाइलिंग में बांटा गया है।' फाइलिंग के तुरंत बाद मस्क ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'आज के बाद आगे के लिए टेस्ला के शेयर बेचने की कोई योजना नहीं है।' फाइलिंग के मुताबिक, अब कंपनी में एलन मस्क की हिस्सेदारी 26 फीसदी रह गई है।

इस बात की जानकारी ऐसे समय पर आई है, जब एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही व्यापार जगत में खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों में से एक की कमान अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स



के हाथों में आ गई है। फोर्ब्स के मुताबिक, एलन मस्क की नेटवर्थ 268 बिलियन डॉलर है। सौदे के हिस्से के रूप में, मस्क ने कहा कि वह 21 अरब डॉलर की इक्विटी प्रतिबद्धता प्रदान करेंगे। वहीं, 26 अप्रैल को टेस्ला के शेयर में 12 फीसदी की गिरावट हुई थी, जो सितंबर 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। गुरुवार को कंपनी का स्टॉक 877151 डॉलर पर बंद हुआ।

ट्विटर की खरीद के लिए बेचे



शेयर्स : विश्लेषकों का कहना है कि टेस्ला के निवेशकों को यह आशंका है कि ट्विटर के कारण मस्क का ध्यान टेस्ला से भटक

जाएगा और इस इलेक्ट्रिक कार कंपनी के संचालन में उनकी दिलचस्पी कम हो जाएगी। ट्विटर की खरीद के लिए धन जुटाने की

## कार्यालय किराये के मामले में दिल्ली-NCR एशिया में नौवा सबसे महंगा बाजार, पहले नंबर पर हांगकांग

प्रमुख कार्यालय स्थलों के किराये के मामले में दिल्ली-NCR एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नौवें स्थान पर है। यहां ऐसे स्थलों का सालाना किराया 6011 डॉलर प्रति वर्गफुट है।

## • जालंधर ब्रीज। जालंधर

प्रमुख कार्यालय स्थलों के किराये के मामले में दिल्ली-NCR एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नौवें स्थान पर है। यहां ऐसे स्थलों का सालाना किराया 6011 डॉलर प्रति वर्गफुट है। अंतरराष्ट्रीय संपत्ति परामर्शदाता कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया ने साल 2022 की पहली तिमाही के लिए एशिया-प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक जारी किया है। इसमें क्षेत्र के 23 शहरों में किराये की जानकारी जुटाई गई है।

इस सूचकांक के मुताबिक, हांगकांग 186 डॉलर प्रति वर्गफुट किराये के साथ पहले स्थान पर मौजूद है। वहीं, 105 डॉलर प्रति वर्गफुट किराये के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर, 10112 डॉलर के साथ टोक्यो तीसरे स्थान पर 9816 डॉलर के साथ सिडनी चौथे स्थान पर और 8418



डॉलर प्रति वर्गफुट किराये के साथ बीजिंग पांचवें स्थान पर है।

नाइट फ्रैंक ने कहा है कि हांगकांग एशिया

का सबसे महंगा कार्यालय बाजार बना हुआ है। दिल्ली-एनसीआर नौवा सबसे महंगा बाजार है, जहां किराया 62 डॉलर प्रति वर्गफुट प्रति साल



(376 रुपये प्रति वर्गफुट प्रति महीना) है।

मुंबई लिस्ट में 15वें नंबर पर मौजूद : मुंबई में किराया 5019 डॉलर प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष, बंगलुरु

2617 डॉलर प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष के साथ क्रमशः 15वें और 21वें स्थान पर हैं।

नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि कोविड संबंधी पारिदृश्य के हटने के बाद से भारत के कार्यालय बाजार परिदृश्य में सुधार आना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब ज्यादा कंपनियां अपने कर्मचारियों को कार्यालय बुला रही हैं।

इसके अलावा आपको बता दें कि हाउसिंग सेक्टर धीरे धीरे महामारी के असर से बाहर निकलने लगा है, वहीं सेक्टर में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान स्थिरता के साथ आना शुरू हो चुका है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) ने जानकारी दी है कि उसने रिहायशी संपत्तियों के लिये आउटलुक की समीक्षा की है और मौजूदा वित्त वर्ष के लिये आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर कर दिया है, रेटिंग एजेंसी के मुताबिक आउटलुक को अपग्रेड करने की मुख्य वजह मांग में बढ़त है। देश के कई हिस्सों में घरों की मांग में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रही है। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इस साल घरों की कीमतों में बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं, घर कर्ज भी महंगे हो सकते हैं।

## टोक्यो में अगले महीने होगी पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात, चीन की चुनौती से निपटने पर चर्चा करेंगे दोनों नेता

क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इसका मुख्य मकसद हिंद-प्रशांत में चीन की चुनौती से निपटना है।

## • जालंधर ब्रीज। दिल्ली

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने दक्षिण कोरिया और जापान जाएंगे। बाइडेन टोक्यो में क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। टोक्यो में वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेता व्यक्तिगत रूप से चीन से निपटने पर चर्चा करेंगे। क्वाड हाउस ने यह जानकारी दी। बाइडेन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करेंगे। क्वाड हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, यह यात्रा स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत के लिए बाइडेन-हैरिस प्रशासन की प्रतिबद्धता को और प्रगाढ़ करेगी। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं।

बाइडेन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। साकी ने कहा, ये नेता हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधों को गहरा करने, आर्थिक संबंधों को बढ़ाने और हमारे निकट सहयोग को विस्तार देने के अवसरों पर चर्चा करेंगे। टोक्यो में राष्ट्रपति बाइडेन क्वाड के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के संबंध अन्य जानकारी जल्द साझा की जाएगी। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इसका मुख्य मकसद हिंद-प्रशांत में चीन की चुनौती से निपटना है।

चीन से होने वाले खतरे को नहीं भूला अमेरिका : अमेरिका ने क्वाड शिखर सम्मेलन के अगले महीने आयोजन करने के ऐलान के साथ दिखा दिया है कि भले ही यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। लेकिन उसका ध्यान अभी भी हिंद-प्रशांत पर टिका हुआ है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चीन से होने वाले खतरे को नहीं भूला है और यूक्रेन के साथ-साथ चीन भी



उसके लिए एक प्रमुख एजेंडा है। हालांकि, अभी तक क्वाड शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय नहीं हो पाया है। यहां गौर करने वाली बात ये है कि क्वाड की पहचान चीन को रोकने वाली शक्ति के तौर पर होती है। लेकिन भारत का मानना है कि चार देशों के इस समूह के जरिए हिंद-प्रशांत में कानून के जरिए शासन चलता है। क्या है क्वाड?

हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया। इसका मकसद आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करना रहा। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद या क्वाड का औपचारिक रूप दिया। 2017 में चीन से खतरे का सामना करने के बाद, क्वाड ने एक नियम-आधारित

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए निर्धारित एक मैकेनिज्म बनाकर अपने उद्देश्यों का विस्तार किया।

क्वाड भारत के लिए चीनी प्रभाव का मुकाबला करने, कोविड के बाद की कूटनीति बढ़ाने, हिंद महासागर में सुरक्षा प्रदान करने और एक नियम-आधारित बहुध्रुवीय दुनिया को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## ट्विटर के बाद अब कोका-कोला की कंपनी खरीदेंगे एलन मस्क! कहा- फिर से कोकिन डालकर बेची जाएगी ड्रिंक्स



दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। इसके बाद से ही ये खबर दुनियाभर में सुविधा बटोर रही है। वहीं, अब मस्क ने इशारा किया है कि वह दुनिया एक और बड़ी कंपनी को खरीदने जा रहे हैं। दरअसल, एलन मस्क ने गुरुवार को ट्वीट किया, वह अब कोका-कोला को खरीदेंगे और उसमें फिर से कोकिन को डालना शुरू कर देंगे। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। जल्द ही ट्विटर पर कोका-कोला ट्रेंड भी होने लगा। महज तीन घंटे में ही मस्क के ट्वीट को 16 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, जबकि 218 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे रिट्वीट किया है।

ट्विटर पर फ्री स्पीच को बढ़ावा देने में यकीन रखते हैं मस्क : वहीं, एलन मस्क और ट्विटर के बीच हुए समझौते के तहत वह ट्विटर को नीचा दिखाने वाला या उसका अपमान करने वाला कोई ट्वीट नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क इन दिनों ट्विटर पर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि ट्विटर को कैसा होना चाहिए। मस्क का मानना है कि ट्विटर को फ्री स्पीच को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन ये उस देश के कानून के तहत होना चाहिए, जहां से ट्वीट किया जा रहा है। उनका कहना है कि कंपनी को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर मस्क चाहते हैं कि ट्विटर डीएम के पास सिग्नल की तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हो, ताकि कोई भी पर्सनल मैसेज की जासूसी या उसे हक न किया जा सके।

कोका-कोला खरीदना नहीं होगा आसान : दूसरी ओर, अगर कोका-कोला की बात करें तो मस्क ने एक बात स्पष्ट कर दी है। वह ये है कि अगर मस्क अटलांटा स्थित कंपनी को खरीदते हैं, तो कोका-कोला की ऑरिजनल रेसिपी का इस्तेमाल फिर से किया जाएगा और इसके जरिए ही ड्रिंक्स को तैयार किया जाएगा। ऑरिजनल रेसिपी में कोकिन का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं, ब्लूमबर्ग ने कहा, 'कोका-कोला के आगे ट्विटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप 284 बिलियन डॉलर है। वहीं एलन मस्क की नेट वर्थ 253 बिलियन डॉलर है। हालांकि मस्क अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी जेफ बेजोस से कोसों दूर आगे खड़े हैं। बेजोस की नेट वर्थ 162 बिलियन डॉलर है।'

